has either given up the subsidy, or the eligible households which have exceeded their quota of 12 cylinders annually, will now have to pay ₹ 737.50 for a single cylinder of gas, up from ₹ 651.50 per cylinder as on February 28, 2017. The alarming increase is aggravated by the fact that it follows on the heels of a vicious ₹ 66.50 per cylinder hike put into effect from February 1, 2017.

Women's ability to keep the home fires burning and manage the household budget has come under severe strain as the fuel costs have gone up dramatically over the last six months. A non-subsidized LPG cylinder that cost ₹ 465.50 in September has risen by ₹ 271, a whopping 58 per cent increase over six instalments.

The move to shift household kitchens from using firewood, coal, or even kerosene stoves to the LPG stove is being vitiated by the current Government policies which are driving up LPG costs to new heights. Since the universal subsidy scheme has been replaced by a targeted one, large number of families who are eligible for subsidized cylinders are now unable to obtain their entitllement.

The Government should roll back this unprecedented hike in the price of LPG cylinders and provide relief to the mass of working-class and middle-class sections by reducing its own indirect tax rates.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over, please.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूं।

Need to include Bhojpuri in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): उपसभापति जी शुक्रिया। इस हाउस और लोक सभा को मिलाकर सरकार ने कम से कम चार बार यह आश्वासन दिया है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। महोदय, जो भोजपुरी भाषा है, हम उसके लिए यह मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि जिसकी, जो भी मातृभाषा है, जिसको उर्दू में मादरी जबान कहते हैं, उस मातृभाषा में कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो अनिवार्य की ही जाए। हम यह पूरे देश की सभी भाषाओं के लिए चाहते हैं।

[श्री अली अनवर अंसारी]

महोदय, हमारी पार्टी की दिल्ली इकाई ने छह पेज का एक पत्र माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को लिखा है। इसे माननीय सदस्य हरिवंश बाबू, रामचंद्र बाबू और हमारे दूसरे लोगों ने मिलकर लिखा है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कीजिए। जब चुनाव आता है, तो बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जाते हैं और बिहार में भी चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता जब गए थे, तो भोजपुरी में एकाध शब्द, लाइन बोल कर लोगों को रिझाने, फुसलाने की बात करते हैं और यह इम्प्रेशन देते हैं कि आप हमें वोट दो और हम सरकार में आएंगे तो तुम्हारी मांग को मान लेंगे।

श्री उपसभापतिः आप थोड़ा भोजपुरी में बात करो।

श्री अली अनवर अंसारीः सर, हम बोलते हैं। यह जवन भोजपुरी भाषा बा, भोजपुरी भाषा बड़ी कड़क भाषा ह, मर्दानगी ई में झलके ला। लेकिन ऊ मर्दानगी ही नइखे, ए में मिठास भी हो ला और मिठास चीनी वाला मिठास ना, गुड़ के भेली वाला मिठास हो ला, ए भोजपुरी में। महापंडित तो एके भईलन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी, पंडित लोग तो बहुत भइल बा। लेकिन महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी जिन्दगी में लिखा कि भोजपुरी के मानने वाले दस करोड़ पूत हैं, दस करोड़ संतान हैं। आज तो दुनिया में वह आबादी बीस-पच्चीस करोड़ हो गई। ठीक है, मैथिली को आपने कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। वह भी हमारी ज़ुबां है, वह भी मीठी ज़ुबां है, लेकिन आप भोजपुरी को भी कीजिए। यह भोजपुरी वीर कुँवर सिंह की ज़ुबां है, यह भोजपुरी शेरशाह शूरी की ज़ुबां है, यह भोजपुरी गंगा-जमुनी तहज़ीब की ज़ुबां है, हिन्दू-मुस्लिम एकता की ज़ुबां है। आप जान लीजिए कि इसको नकारिएगा, तो भोजपुरिया लोग दिल पर ले लेते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. Time is over.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

†جناب جاوید علی خان (اترپردیش): مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع سے سمبدّ کرتا ہوں۔

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI RANVIJAY SINGH JUDEV (Chhattisgarh): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Ali Anwar Ansari.

---

† Transliteration in Urdu script.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Ali Anwar Ansari.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Ali Anwar Ansari.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Ali Anwar Ansari.

DR. TAZEEN FATMA (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Ali Anwar Ansari.

कुछ माननीय सदस्यः महोदय, हम भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Now, Shri Mohd. Ali Khan.

Concern over the pendency of reimbursement of medical bills of private hospitals empanelled under CGHS

SHRI MOHD. ALI KHAN (Andhra Pradesh): Sir, I wish to bring to your notice that certain private and corporate hospitals are exploiting the CGHS beneficiaries, in spite of prescribing package rates and firm rules, in the following ways: (a) They compel the patients to undergo certain investigations, outside the package, at the expense of the patients, by threatening them with dire health consequences. (b) They refuse the CGHS card, under one or the other pretext, and advice the CGHS beneficiaries to undergo treatment with their own expenses and later submit the claim for reimbursement and subject the patients to unnecessary diagnostic tests by making them pay from their hard earned savings. I, therefore, request the Government to thoroughly scrutinize and audit all the pending medical bills by obtaining information from individual beneficiaries about the expenses incurred by them for the treatment outside the package cost and also confine the bills to the extent of package rate prescribed by CGHS.

चेयरमैन साहब, पूरे भारत देश के अंदर इन प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने अपना एक उसूल बनवा लिया है। सीजीएचएस बावस्ता कई लाखों, करोड़ों बेनिफिशरीज़ हैं, वांटेडली और अन-वांटेडली उनका टेस्ट करवा कर करोड़ों रुपया मरकज़ी सरकार के फंड से, स्टेट सरकारों के फंड से ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं। तो मरकज़ी सरकार से और खुसूसन हेल्थ मिनिस्ट्री से मेरी यह डिमांड है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लगाम लगाने के लिए इनका सेंट्रल ऑडिट करवाना जरूरी है।

इस मौके से मैं आज आपका फायदा उठाते हुए मोहतरमा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहन सुषमा स्वराज जी को उनकी सेहतयाबी के लिए खुदा और भगवान से दुआ करते हुए कहूंगा कि आज वे हाउस में आई हैं। मैं उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ। जय हिन्द।